छावनियों में सेवा का नया पड़ाव: रक्षा-सामाजिक न्याय मंत्रालयों का वृद्धजन MoU



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में DGDE और MoSJE के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए। उद्देश्य छावनी (cantonment) क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर केंद्र और वृद्ध-आवास (Senior Citizen Homes) स्थापित व मजबूत करना तथा जेरियाट्रिक केयरगिवर (geriatric caregiver - वृद्ध-देखभाल करने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति) का कौशल-प्रशिक्षण देना है। अवसर विशेष था - सामरिक स्थान विभाग (Defence Estates Department) अपनी स्थापना (1926) के 100 वर्ष पूरे कर अपनी शताब्दी मना रहा है।

परिचय: DGDE और AVYAY

DGDE (Directorate General of Defence Estates): रक्षा मंत्रालय का विभाग जो छावनी भूमि और छावनी बोर्डों के नागरिक प्रशासन का प्रबंधन करता है। छावनी बोर्ड अपने बजट से कुछ डे-केयर केंद्र और वृद्ध-आवास पहले से चला रहे हैं।

AVYAY (अटल वयो अभ्युदय योजना - Atal Vayo Abhyuday Yojana): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय योजना, जिसका लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों का सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय वृद्धावस्था (active ageing) है; इसी योजना से इस पहल को वित्तीय सहायता मिलेगी।

मुख्य भाग: MoU के प्रावधान

- **वित्तपोषण:** MoSJE, AVYAY के अंतर्गत वित्तीय सहायता देगा, जिसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से चलाए जा रहे मौजूदा डे-केयर केंद्रों और वृद्ध-आवासों के संचालन-रखरखाव का समर्थन भी शामिल है।
- **नए केंद्र:** DGDE ने आठ छावनियाँ चिन्हित की हैं, जहाँ नए डे-केयर केंद्र खोले जा सकते हैं; मौजूदा पाँच छावनियों के डे-केयर केंद्र और दो छावनियों के वृद्ध-आवास भी निधि-उपलब्धता के अनुसार विस्तारित होंगे।
- **दायित्व-विभाजन:** DGDE और छावनी बोर्ड परिसर और मूलभूत संरचना (बिजली, जल, स्वच्छता) उपलब्ध कराएँगे; MoSJE वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण-मॉड्यूल और परिचालन-सहयोग देगा।
- **केयरगिवर-प्रशिक्षण:** बढ़ती वृद्ध-जनसंख्या को देखते हुए युवाओं को जेरियाट्रिक केयरगिविंग में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का पूल बनेगा।
- **संयुक्त कार्य-समूह:** दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का Joint Working Group समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी करेगा।
- **सामाजिक लेखा-परीक्षा:** रक्षा मंत्री ने केंद्रों और आवासों की सेवा-गुणवत्ता जाँचने के लिए सामाजिक लेखा-परीक्षा (social audit) का आह्वान किया।

कौन-सी छावनियाँ कवर होंगी

- **मौजूदा डे-केयर केंद्र (5):** अंबाला (हरियाणा), देवलाली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्य प्रदेश), रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड)।
- **मौजूदा वृद्ध-आवास (2):** अयोध्या और लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
- **नए केंद्र (8):** बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झाँसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली।
- **केयरगिवर-प्रशिक्षण (12 छावनियाँ):** बैरकपुर, बेलगाम, झाँसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोज़पुर और जालंधर।

परीक्षा के लिए महत्व

प्रिलिम्स की दृष्टि से: MoU के पक्षकार (DGDE-MoSJE), AVYAY योजना, 1926 की शताब्दी, छावनी-सूची - प्रत्यक्ष प्रश्न-विषय।

मुख्य परीक्षा की दृष्टि से: 'Whole of Government' दृष्टिकोण - दो मंत्रालयों के संसाधनों (रक्षा-भूमि/परिसर + नीति/वित्त) का मिलकर उपयोग; वरिष्ठ-कल्याण और सक्रिय वृद्धावस्था - GS-II के उदाहरण।

आगे की राह

Joint Working Group के गठन से केंद्रों की स्थापना-समयसीमा तय होगी। AVYAY से नियमित वित्त आने पर छावनी बोर्डों की रक्षा-अनुदान पर निर्भरता घटेगी और सेवाएँ टिकाऊ होंगी; केयरगिवर-प्रशिक्षण से युवाओं को रोज़गार-पथ भी मिलेगा।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न1. DGDE-MoSJE समझौता-ज्ञापन (16 नवंबर 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: इसका उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में डे-केयर केंद्र और वृद्ध-आवास स्थापित करना है
कथन 2: इस पहल का वित्तपोषण AVYAY योजना से होगा
कथन 3: MoU पर गृह मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2

व्याख्या: कथन 1 सही है: छावनी क्षेत्रों में डे-केयर केंद्र/वृद्ध-आवास और केयरगिवर-प्रशिक्षण इस MoU के उद्देश्य हैं। कथन 2 सही है: वित्तीय सहायता अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) से मिलेगी। कथन 3 गलत है: हस्ताक्षर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुए, गृह मंत्री की नहीं।

प्रश्न2. सामरिक स्थान विभाग (Defence Estates Department) अपनी कौन-सी वर्षगाँठ मना रहा है?

(a) 75वीं

(b) 90वीं

(c) शताब्दी (100वीं)

(d) 125वीं

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c) शताब्दी (100वीं)

व्याख्या: विभाग की स्थापना 1926 में हुई थी; 2026 में वह अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर शताब्दी-समारोह मना रहा है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

DGDE-MoSJE MoU 'Whole of Government' दृष्टिकोण का उदाहरण है। स्पष्ट कीजिए और वरिष्ठ नागरिक-कल्याण में ऐसे अंतर-मंत्रालयी सहयोग की संभावनाओं पर टिप्पणी कीजिए। (सामान्य अध्ययन-II; 150 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: 16 नवंबर 2026 के MoU और उसके उद्देश्यों (डे-केयर, वृद्ध-आवास, केयरगिवर-प्रशिक्षण) का परिचय।

मुख्य भाग में: 'Whole of Government' का अर्थ - DGDE के परिसर/छावनी बोर्ड-ढाँचे और MoSJE की योजना/वित्त/प्रशिक्षण का संयोजन; मौजूदा सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग; सामाजिक लेखा-परीक्षा से गुणवत्ता-निगरानी; बढ़ती वृद्ध-जनसंख्या के संदर्भ में केयरगिवर-पूल से रोज़गार-सृजन।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष रखें कि संस्थागत सहयोग सक्रिय वृद्धावस्था को सुनिश्चित करने का टिकाऊ मार्ग है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: DGDE और MoSJE ने 16 नवंबर 2026 को MoU किया, जिससे छावनी क्षेत्रों में डे-केयर केंद्र/वृद्ध-आवास AVYAY योजना की सहायता से बनेंगे और जेरियाट्रिक केयरगिवर-प्रशिक्षण दिया जाएगा; हस्ताक्षर रक्षा मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री की उपस्थिति में हुए।

प्रश्न: AVYAY क्या है?

अटल वयो अभ्युदय योजना - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना, जो वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए वित्तीय सहायता देती है।

प्रश्न: MoU में दोनों पक्षों के दायित्व क्या हैं?

DGDE/छावनी बोर्ड परिसर और मूलभूत संरचना देंगे; MoSJE वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण-मॉड्यूल और परिचालन-सहयोग देगा।

प्रश्न: कौन निगरानी करेगा?

दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का संयुक्त कार्य-समूह (Joint Working Group) समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी करेगा।

स्रोत

- PIB - MoD & MoSJE ink MoU to strengthen welfare of senior citizens in Cantonment areas (16 नवंबर 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336804&lang=2&reg=48

संबंधित लेख (आंतरिक लिंक)

- आधार फेस प्रमाणन बनाम दिव्यांगजन की पहुँच: सुप्रीम कोर्ट की अवमानना चेतावनी